

डीपीसी अगले महीने होगी, वरिष्ठता सूची के आधार पर अफसरों को मिलेगा मौका पदोन्नति के लिए पैनल तैयार, 21 अफसर बनेंगे आईएस-आईपीएस

भोपाल, दोपहर मेट्रो। मध्यप्रदेश के राज्य प्रशासनिक और राज्य पुलिस सेवा के 21 अफसरों के लिये जल्द गड्ड न्यूज आ सकती है। क्योंकि इन्हें आईएस-आईपीएस संग्रह में पदोन्नति मिलने वाली है। राज्य प्रशासनिक सेवा के 16 और राज्य पुलिस सेवा के 5 अफसरों का प्रमोशन कर अखिल भारतीय सेवा में शामिल करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। जानकार सूत्रों का कहना है कि जून के दूसरे सप्ताह में यूपीएससी में विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक संभावित है। जिसमें इन अफसरों को आईएस-

आईपीएस अवॉर्ड की मंजूरी मिलेगी। इस साल आईएस के लिए वरिष्ठता सूची के आधार पर 2006 और 2007 बैच के अफसरों को मौका मिला है। आईपीएस के लिए 1997-98 बैच के अफसरों के नाम शामिल किए गए हैं। उल्लेखनीय है एक पद के लिए तीन नामों का प्रस्ताव तैयार किया जाता है। इस साल 2023 और 2024 के 8-8 यानी 16 पदों के लिए डीपीसी होगी। दरअसल, 2023 में जिन आठ पदों के लिए डीपीसी होनी थी, वह यूपीएससी को देर से प्रस्ताव भेजने के कारण नहीं हो पाई थी। सामान्य प्रशासन विभाग ने डीपीसी के लिए प्रस्ताव तैयार कर मुख्य सचिव के अनुमोदन के लिए भेजा था।



अधिकारियों ने सीएम से की थी मुलाकात इसमें एसएस के पदों के साथ नॉन एसएस (अन्य सेवा) के पदों का भी प्रस्ताव भेजा गया था। इसको लेकर राज्य प्रशासनिक सेवा संघ ने विरोध जता दिया तब एसएस अधिकारियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और विरोध में ज्ञापन सौंपा था। ऐसा 2021-2022 में भी हुआ था। बताया जाता है कि राज्य पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा के लिए होने वाली डीपीसी (विभागीय पदोन्नति समिति) की बैठक जून के पहले सप्ताह में होने की उम्मीद है। गृह विभाग ने पिछले सप्ताह यूपीएससी को पैनल तैयार करके भेज दिया है। सूत्रों के मुताबिक, 5 पदों के लिए 1997 और 1998 बैच के 15 अफसर सिलेक्ट किए गए हैं। इसमें से दो अफसरों की जांच के कारण लिफाफे बंद रह सकते हैं।

9 साल से अटके एचआर पर की बात

कर्मचारियों के बीच पहुंचकर सीएम ने काम अटकाने और लटकाने की शैली को कोसा

भोपाल, दोपहर मेट्रो। कर्मचारियों के बीच पहुंचकर सीएम मोहन यादव ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। उन्होंने कर्मचारियों से कहा कि 9 सालों से आपका एचआरए लटका हुआ था। मैं ये देखकर दुखी होता था। जिनके हक की चीज है, उन्हें ये समय पर देनी चाहिए। वो सारे अंतर जिनके माध्यम से जबरदस्ती से अटकाना-लटकाना, मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं था। ये चीजें तब मिलें जब बोला जाए इससे बेहतर है कि पहले ही दी जाए। मैं इस मामले में थोड़ा भाग्यशाली हूँ कि आप लोगों को ज्ञापन देने नहीं आना पड़ा। मैंने खुद ही बढ़ा दिया। रवींद्र भवन में राज्य कर्मचारी संघ के कार्यक्रम में उन्होंने यह बात कही। इस मौके पर मुख्यमंत्री यादव का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भाजपा विधायक भगवान दास सबनानी, नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी के साथ ही कर्मचारी संघ और भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी भी मौजूद थे। इस मौके पर कर्मचारियों के डीए को लेकर सीएम मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के समान डीए मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का एक वाक्य है डबल इंजन की सरकार। तो आगे जो इंजन लगा है, वह तेज चलेगा तो हमें भी तेज चलना पड़ेगा। सीएम ने कहा- स्थानांतरण नीति के बारे में भी ध्यान रखा। ट्रांसफर करेगे लेकिन तब करेगे जब सबका समय आएगा। जब बच्चों की छुट्टियां हो जाएं। हम थोड़ा आने जाने की व्यवस्था बना लें इसलिए गर्मी की छुट्टियों का इंतजाम किया। भले जो भी सहन करना पड़ा। नए-नए मुखिया को कितना सहन करना पड़ता है आप सब जानते हैं। लेकिन हमने कहा समय आएगा जरूर कर देंगे। आपके बिना कहे एक महीने का समय दिया।

कर्मचारी संघ ने सीएम डॉ. यादव का किया सम्मान



रवींद्र भवन में आयोजित कार्यक्रम में मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री मोहन यादव का अभिनंदन किया। फोटो निर्मल व्यास

मुखिया अव्यवस्था को दुरुस्त करे

सीएम ने कहा कि हमारे बीच की परस्पर व्यवस्थाओं के अंतर्गत हम काम करते हैं। सरकार और सरकार के मुखिया और व्यवस्थाओं का एक ही मतलब है कि हम अपनी व्यवस्थाओं में सुव्यवस्था स्थापित करें। कहीं अव्यवस्था या

दुरावस्था है, कमी है तो उसे दुरुस्त करें। सीएम ने कहा- मैं प्राधिकरण में रहा, टूरिज्म में रहा, शिक्षा मंत्री के रूप में काम करके आपके बीच से निकला तो मुझे इस बात का एहसास है कि हम निर्णय कुछ भी कर लें, लेकिन निर्णय

का नीचे क्रियान्वयन कराने की जो एजेंसी है, उस निर्णय को नीचे अंजाम तक पहुंचाने वाले लोगों के मन में कोई असंतोष है या उनकी व्यवस्था बिगड़ी है तो हम कितनी भी बात कर लें उस बात का नीचे असर आएगा ही नहीं।

उच्च शिक्षा : अंतिम तिथि तक पहुंचे 1830 आवेदन, 1260 आवेदन प्रोफेसरों ने किए

भोपाल। स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा सहित अन्य विभागों में तबादलों को लेकर प्रक्रिया जारी है। उच्च शिक्षा विभाग ने आवेदन जमा करा लिए गए हैं। विभाग को अंतिम तिथि तक एक हजार 830 आवेदन मिले हैं। इसमें 68 फीसदी आवेदन प्रोफेसरों ने किए हैं। शेष आवेदन खेल अधिकारी, ग्रंथपाल और अन्य कर्मचारियों द्वारा किए गए हैं। इसमें अधिकतम आवेदन उन प्रोफेसरों के हैं, जिन्होंने 2019 में नियुक्ति हासिल की थी। उनकी परिवीक्षा समाप्त हो गई है। इसलिए वे नये स्थान पर जाना चाहते हैं। विभाग ने जमा आवेदनों की स्क्रूटनी शुरू कर दी है। उच्च शिक्षा विभाग को 31 मई तक स्थानांतरण करने हैं। जल्द ही स्थानांतरण के आदेश ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। पहले विभाग आवेदनों की स्क्रूटनी करेगा। इसमें देखा जाएगा कि कौन से अधिकारी व कर्मचारी कितने समय से एक ही स्थान पर जमे हुए हैं। यहां तक उनके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज तो नहीं कराई गई। लंबे समय से एक स्थान पर जमे कर्मचारी और अधिकारी कालेज और विश्वविद्यालयों को छोड़ना चाहते हैं। इसलिए समूचे राज्य से विभाग को अंतिम तिथि तक एक हजार 830 आवेदन मिले हैं।

आज राज्य शिक्षा केंद्र कर सकता है मामले में बड़ी कार्यवाही, जांच डीपीसी शर्मा की मुश्किलें बढ़ी, अब निजी स्कूल संचालक और जपिप अध्यक्ष ने भी की शिकायत

भोपाल, दोपहर मेट्रो। जिला शिक्षा केंद्र में पदस्थ जिला परियोजना समन्वयक (डीपीसी) ओपी शर्मा की शिकायतें मुख्यालय पहुंचने और कथित ऑडियो वायरल होने के बाद अब डीपीसी शर्मा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इधर मामले में डीपीसी शर्मा के विरोध में निजी स्कूल संचालक और नेता भी मैदान में उतर आए हैं और शिकायतें की गई हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष रामकुंवर नौरंग सिंह गुर्जर और जपिप उपाध्यक्ष मोहन सिंह जाट ने प्रभारी मंत्री चैतन्य काश्यप को डीपीसी शर्मा को हटाने के लिए पत्र लिखा है। शर्मा का कार्य व्यवहार जनप्रतिनिधियों के प्रति ठीक नहीं : जपिप अध्यक्ष और

उपाध्यक्ष ने पत्र में लिखा है कि डीपीसी शर्मा का कार्य व्यवहार जनप्रतिनिधियों के प्रति ठीक नहीं है। इससे लगातार शिकायतें मिल रही हैं। इनके द्वारा कार्य में लापरवाही से शासन की योजनाओं का लाभ छात्रों को समय से नहीं मिला पा रहा है। जपिप अध्यक्ष गुर्जर और उपाध्यक्ष जाट ने अपने पत्र में शर्मा को हटाकर विकास खंड स्तरीय समन्वयक बालेन्द्र सिंह को प्रभार सौंपने की बात कही है। पत्र में कहा गया है कि डीपीसी शर्मा नवीनीकरण के नाम पर स्कूलों से करोड़ों की राशि वसूल रहे हैं। उनके ऑफिस में दो लोग ऐसे पदस्थ हैं जो शिक्षा विभाग के नहीं हैं। ये स्कूल संचालकों को कमियां बताकर उनसे पैसे मांगते हैं।

मेट्रो एंकर मप्र गेहूं उपाजर्जन में देश में दूसरे स्थान पर, मंत्री ने टी बधाई, बोले

योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बर्दाशत नहीं

दोपहर मेट्रो, भोपाल प्रदेश में इस वर्ष गेहूं उपाजर्जन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। प्रदेश अब पूरे देश में गेहूं उपाजर्जन में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। यह जानकारी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने प्रभार के जिले गुना में जिला अधिकारियों की समीक्षा बैठक के दौरान दी। मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि इस वर्ष गेहूं उपाजर्जन में 60 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में एक बड़ी छलांग है। उन्होंने इसे किसानों के प्रति राज्य सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता और सुनियोजित नीति का परिणाम बताया। मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि हमारे प्रयासों का



मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना और उपाजर्जन प्रक्रिया को पारदर्शी एवं सुविधाजनक बनाना है। उन्होंने 60 प्रतिशत से अधिक गेहूं उपाजर्जन पर उपाजर्जन से जुड़े विभाग के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का आभार जताया। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बिल्कुल बर्दाशत नहीं की जाएगी। गौरतलब है कि राज्य सरकार की सक्रिय भूमिका, समय पर समर्थन मूल्य की घोषणा तथा सुचारु परिवहन और भंडारण व्यवस्था ने इस उपलब्धि में अहम भूमिका निभाई है।

उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी हुए सम्मानित

मंत्री राजपूत ने जल-गंगा संवर्धन अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया। डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी सीएमओ सुश्री मंजूषा खत्री, एसडीओ पीएचई टीएल मेहरा एवं उपयंत्री जनपद पंचायत आरोन चंदन शुक्ला को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। साथ ही राज्य स्तरीय मेरिट सूची में स्थान पाने वाले छत्र शैलेन्द्र धाकड़, कु. पूर्णिमा अडावकर एवं राष्ट्रीय ओलंपियाड प्रतियोगिता में चयनित नमन लोधी को भी सम्मानित किया गया। बैठक में कलेक्टर किशोर कन्याल ने बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराए गए ग्रामिणों की जानकारी दी। उन्होंने विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की भी जानकारी दी।

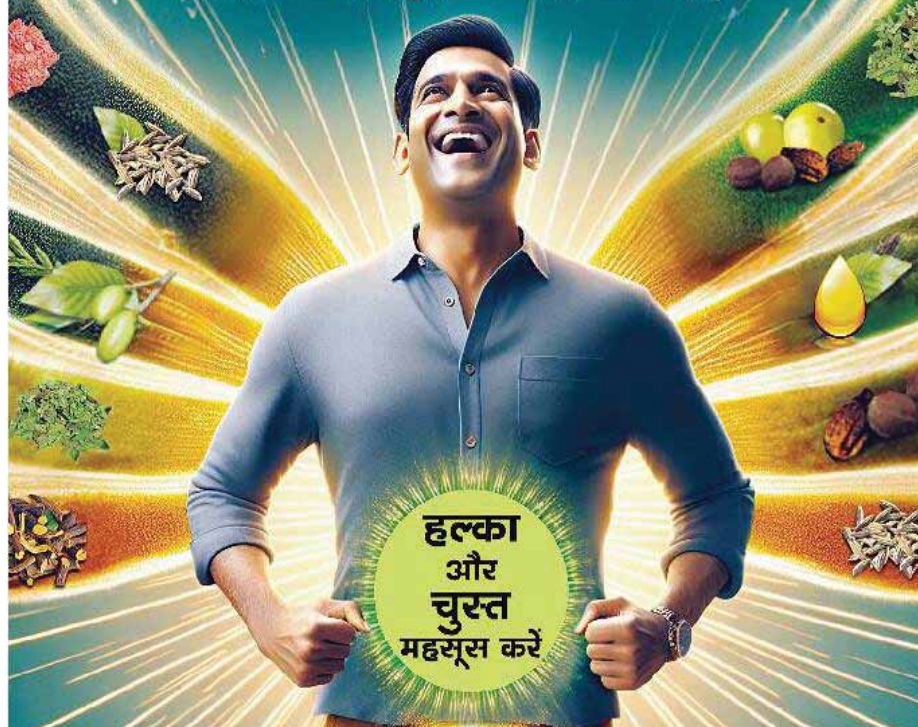
मोबाइल कोर्ट से न्याय हो रहा सुलभ

बैठक में बताया गया कि मोबाइल कोर्ट के माध्यम से जमीनी विवाद, अतिक्रमण और सीमांकन जैसे पुराने लंबित प्रकरणों के चरित्र निपटारे किए जा रहे हैं। इस दौरान दोनों पक्षों की सहमति से मौके पर ही समाधान किया जा रहा है, जिससे जनता को न्याय सुलभ हो रहा है।

कब्ज से आज़ादी

इंडु नित्यम

रातोंरात आराम से राहत गैस - एसिडिटी से राहत पेट साफ़ करे बिना पेट मरोड़



1 बार में असरदार राहत

इंडु नित्यम आयुर्वेदिक कब्जनाशक टैबलेट

